LOK SABHA

Monday, February 17, 1975/Magha 28, 1896 (Saka)

The Lok Sabha met at Twenty-five Minutes past Twelve of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

MR. SPEAKER: The new Member has not arrived.

PRESIDENT'S ADDRESS

SECRETARY-GENERAL: Sir, I beg to lay on the Table a copy of the President's Address to both Houses of Parliament assembled together on the 17th February, 1975.

President's Address

माननीय सदस्यगण,

मै आप सब का स्वागत करता हू और अगले वर्ष फिर मेहनत और लगन के साथ राष्ट्र की सेवा करने का बुलावा देता हू ।

2 पिछले चार वर्षो मे नागहानी और भारी चुनौतियो का हिम्मत से मुकाबला करने के बाद हम बडे साहस के साथ यह वर्ष शुरू कर रहे है । लगातार बढती हुई कीमतो को देखते हुए, 1974 मे सरकार की सब से बडी चिन्ता यह रही कि अर्थ-व्यवस्था को पायदार बनाया जाए । मुद्रा-स्फीति पर काबू पाने के लिए सरकार ने एक व्यापक नीति अपनाई और जुलाई, 1974 से इसे अमल में लाया गया ।

3. अधिक से अधिक साधन जुटाने और गैर-योजना खर्च मे कमी करने के अलावा एक उचित मुद्रा-नीति के जरिये मुद्रा-प्रसार पर रोक लगाई गई । स्मगलिंग, जमाखोरी और टैक्स इवेजन जैसे आर्थिक अपराधों तथा कम मिलने वाली चीजों का नकली माल बनाने वालों के खिलाफ एक जोरदार मुहिम चलाई गई । डिविडेंडस की आमदन को सीमित करके और बढ़ाई गई मजदूरी, वेतन और महगाई भत्ते के एक हिस्से को रोके रख कर कन्स्यूमर खर्च को काबू मे रखा गया । सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत किया गया और अनाज, जरूरी कच्चा माल और दूसरे सामान को काफी मात्रा मे आयात करने का बन्दोबस्त किया गया । 1974–75 की सालाना योजना पर फिर से गौर किया गया और उत्पादन बढाने की गर्ज से जरूरी क्षेत्रों मे खर्च किए जाने वाली रकम को बढाया गया । पावर प्लांटस, रेल ट्रासपोर्ट, कोयला उत्पादन, इस्पात प्लांटस और दूसरे सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों की क्षमता को पूरी तरह काम मे लाने के लिये जोरदार कार्यवाई की गई ।

4. इन सब कार्रवाइयो के नतीजे सितम्बर, 1974, के आखिर मे सामने आने शुरू हुए । कई राज्यों में वर्षा की कमी की वजह से खरीफ की फसल तसल्ली बख्श न होते हुए भी कीमतें गिरनी शुरू हुई और मुद्रा-स्फीति को बढ़ावा देने वाले जरिये कमजोर पड़ने लगे । जरूरियाते जिंदगी की चीजों के मिलने मे सुधार हुआ है और रबी की फसल अच्छे होने के आसार है ।

5. इस माली साल के पहले नौ महीनों में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है । थरमल प्लांटस से चौदह फी सदी ज्यादा बिजली पैदा की जा रही है और डी० वी० सी० प्लांट्स से

बिजली पैदा करने मे चौतीस फी सदी की बढ़ोतरी काबले जिकर है। क्योकि कई राज्यो म फिर भी बिजली की कमी पाई जाती है, पावर प्रोजैक्ट्स के पूरा करने के काम को जोरो से हाथ मे लिया जा रहा है। 1974-75 मे लगभग बीस लाख कि० वा० बिजली की क्षमता बढाई जा रही है और तीस लाख अगले वर्ष म बढाई जाएगी। इस वर्ष एक करोड टन ज्यादा कोयला पैदा होगा। इस्पात का उत्पादन बढ रहा है और सरकारी क्षेत्र के इजीनियरिंग उद्योग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अधिक रेल वैगन रोजाना चलाए जा रहे हैं।

6 मै मजदूरो, किसानो और दूसरे तबके के लोगो को बधाई देता हू, जिन्होन अर्थ-व्यवस्था को पायदार बनाने के सरकारी प्रोग्रामो के समर्थन मे पुख्ता इरादे, साहस और राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुसार कार्य किया।

7 सरकार यह जानती है कि अभी आत्मसतोष नही हो सकता है, क्योकि अर्थ-व्यवस्था के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रो म पूर्ति और माग के बीच अभी भी भारी असतुलन है। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति के बारे मे भी कुछ यकीन से नही कहा जा सकता।

8. मुद्रा-सम्बन्धी और माली सुधार के लिये जो कदम उठाये गये और आर्थिक अपराधो के खिलाफ जो कार्यवाई कि गई है उसे जोरो से जारी रखा जाएगा साथ साथ सरकार यह कोशिश करेगी कि जरूरी क्षेत्रो के इन्फास्ट्रक्चर मे जो कमिया है, उन्हे दूर करने के लिये ठोस कदम उठाये जाये और उत्पादन बढ़ाया जाय। हम विकासशील देशो और ऐसे विकसित देशों, जिन्होने हमारी समस्याओ को समझने का परिचय दिया है, के सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे एक न्यायपूर्ण और बायबल अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए अपना काम जारी रखेगे।

9 तेल, अनाज और रासायनिक खाद की कीमते अचानक बढ जाने से हमे काफी धक्का लगा है। आम जरूरत की चीजो पर असर पडा है और इस से जनता को काफी कठिनाइयो का सामना करना पडा है। विदेशी-मुद्रा का काफी निकासन हुआ है। 1974-75 के पहले आठ महीनो मे एक्सपोर्ट अर्निग 36 फी सदी बढी। फिर भी यह नुमाया बढोतरी फारन एक्सचेज की कमी को पूरा करने के लिये काफी नही है। तेल आयात करने वाले विकासशील देशो की समस्याये हल करने के लिए खास प्रयास और बन्दोबस्त जरूरी है। इस मामले मे तेल निर्यात करने वाले कुछ देशो ने हमारी मदद की है। अन्तर्राष्ट्रीय सतह पर भी कुछ कार्यवाई की गई है। लेकिन हालात को देखते हुए ये उपाय काफी नही है। यह मानना होगा कि विकासशील देशो की अर्थ व्यवस्था को भारी नुकसान पहुचा है और इसे ग्लोबल पैमाने पर दुनिया के सभी देशो के अर्थ-पूर्ण सहयोग से पूरा करना होगा। बाइलेट्रल नैगोसियेशन्स और इटरनेशनल फोरम्स के जरिये हम इस दिशा मे उचित पहल जारी रखेगे।

10 तेल का उत्पादन बढाने और कोयले के इस्तेमाल पर जोर देने के अलावा, हम ने तेल की खोज का काम प्राथमिकता के आधार पर शुरू कर दिया है। बम्बई हाई क्षेत्र मे जो खोज की गई है उन के नतीजे बहुत ही आशाजनक है। सरकार ने यह फैसला किया है कि इस तेल-क्षेत्र का जल्दी से विकास किया जाए ताकि उत्पादन शुरू हो सके। ऐसी योजना बनाई जा रही है कि 1976 मे उत्पादन शुरू हो जाए और अगले चार वर्षों मे इस क्षेत्र से एक रोकड़

टन का उत्पादन हो सके । जल व थल दोनों ही इलाको मे तेल उत्पादन का भविष्य बहुत आशाजनक है ।

11 पाचवी पच वर्षीय योजना के बारे मे कुछ चिन्ता होना वाजबी है । योजना का एक ढाचा होता है और उद्देश्यो की एक सुसगत प्रणाली होती है । इस के साथ तफसीलें प्रोग्राम भी होता है जिसमे लक्ष्यो और उनको प्राप्त करने के लिए आवश्यक साधनो का पता चलता है । पाचवी योजना के बुनियादी ढाचे और इस के लक्ष्यो मे कोई हेर फेर नही किया गया है । साथ ही देश और विदेश के आर्थिक क्षेत्रो मे अनोखी घटनाओ को देखते हुए अपने प्रोग्राम मे कुछ रद्दोबदल करने की जरूरत है । इसी बीच 1975–76 की वार्षिक योजना तैयार की जा रही है, जिस मे अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने और जरूरी क्षेत्रो–कृषि उत्पादन, सिचाई, रासायनिक खाद, बिजली, इस्पात, कोयला, और तेल खोज मे अधिक धन राशि लगाने पर बल दिया जा रहा है । यह भी प्रस्ताव है कि विकास के उन प्रोग्रामो को बढावा जाए जिन मे कम विकसित खण्डो और कमजोर वर्गों, जिनमे शड्यूल्ड कास्टस और शड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग भी शामिल है, को फायदा पहुचे । स्माल फार्मर्स डवलेपमेंट एजेंसी और मारजिनल फार्मर एण्ड एग्रीकल्चरल लेबर, सूखा पडने वाले क्षेत्रो और कमाड एरियाज के प्रोग्रामो को बढाया जा रहा है ।

12 1974 के राष्ट्रीय प्रयासो की समीक्षा परमाणु क्षेत्र मे अपनी महान तरक्की का जिक्र किये बिना पूरी नही होगी । 18 मई 1974 को जमीन के नीचे परमाणु विस्फोट किया गया था । मै इस महान उपलब्धि के लिए परमाणु वैज्ञानिकों और इजीनियरो को बधाई देता हू । हमने फिर से प्रतिज्ञा की है कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग केवल शाति के लिए ही किया जाएगा और इसके लिये सभी देशो ने हमारी सराहना की है । सरकार आर्थिक तरक्की लाने के लिये साइंस और टैक्नालोजी को महत्वपूर्ण स्थान देती रहेगी ।

13. मुझे खुशी है कि भारत सरकार के प्रतिनिधियो और जम्मू-कश्मीर के नेताओं के साथ व्यापक रूप से हुई बातचीत के ठोस नतीजे निकले है । इस सम्बन्ध मे सरकार जल्दी ही घोषणा करेगी । हमारी कामना है कि राष्ट्र के अभिन्न अंग के रूप मे जम्मू-कश्मीर के लोग तेजी से तरक्की करे ।

14 माननीय सदस्यगण, जब राष्ट्र महान चुनौतियो का मुकाबला करने के लिये जी-तोड कोशिश कर रहा है, यह दुख की बात है कि कुछ जमातो के लोग जनता के सकल्प को कमजोर करने और सयुक्त तथा समान उद्देश्य, जिसकी इस वक्त बहुत जरूरत है, को निष्फल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे है । उन का दावा है कि उनका लक्ष्य पूर्ण क्रांति लाना और भ्रष्टाचार मिटाना है लेकिन असल मे नतीजा यह रहा कि हिसा फैली और राजनीतिक और आर्थिक जीवन छिन्न-भिन्न हुआ । सरकार इस बात को पूरी तरह जानती है कि राष्ट्रीय जीवन के बहुत से क्षेत्रों मे सुधार की जरूरत है । असल मे हमारा उद्देश्य है समाज मे परिवर्तन लाना और जन जीवन के स्वभाव मे सुधार लाना । लोकतत्र की प्रणाली का यही सार है कि परिवर्तन ज्यादा से ज्यादा विचार-विमर्श और आपसी समझौते के आधार पर ही लाया जाय । जब तक काबिले अमल कोई बेहतर तरीका सामने न रखा जाए मौजूदा व्यवस्था और संस्थाओ को छिन्न भिन्न करने से हमारे देश की पायदारी और तरक्की को खतरा होगा ।

15. सरकार चाहती है कि लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक पर, जो कुछ समय से आपके सामने है, विचार हो और इस वर्ष इसे अंतिम रूप दिया जाए। इससे राजनीतिक प्रशासकों और प्रशासन में भ्रष्टाचार से निपटने का कानूनी आधार मिलेगा। सरकार चुनाव-कानून में संशोधन के प्रस्तावों पर राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ जल्दी ही विचार-विमर्श करेगी। जो भी सुधार लाए जाएं वे ऐसे होने चाहिए कि जहां तक हो सके उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिले और उनसे हमारे संविधान में रखी गई संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली मजबूत हो।

16 शिक्षा के मामले में भी, सरकार ने इम्तेहान के तरीकों में सुधार लाने, सैकंडरी एजुकेशन को काम धन्धों का आधार देने उच्चतर शिक्षा के लिए एनरोलमेंट का असूल इख्त्यार करने और गैर-औपचारिक शिक्षा की प्रणाली लागू करने के प्रोग्राम बनाए है। पिछले तजुर्बे से पता चलता है कि शिक्षा के सुधार की योजनाओं में तब तक तेजी नहीं आती जब तक राज्य सरकारें, शिक्षक, माता-पिता और विद्यार्थी इन्हें स्वीकार नहीं करते। इसी बीच लाखों नौजवानों के पढ़ाई के जीवन में काफी बेचैनी देखने में आई है। राज्य सरकारों ने सुधार के कुछ प्रोग्रामों को अमल में लाने के उपाय किए है। हम यह चाहते हैं कि तालीम के तरीकों में अगर कोई बुनियादी तबदीली लानी है तो इसे पूरी तरह विचार-विमर्श के बाद लाया जाय।

17. मैं सभी तबके के लोगों से अपील करता हूं कि वे इन बुनि ादी सवालों पर संजीदगी से विचार करें, ठोस और रचनात्मक सुझाव सामने रखें और हल ढूंढने के लिए सरकार को सहयोग दें। लोकतन्त्र का यही तरीका है। कोई और तरीका अपनाने से गड़बड़ फैलेगी और कोई कारआमद नतीजा न निकलेगा।

18. अब मैं सिक्किम की घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा। अप्रैल, 1974 में वहां पहली बार चुनाव हुए। सर्व-सम्मति से विधान सभा के प्रस्ताव पर 4 जुलाई, 1974 को चोग्याल की घोषणा के आधार पर नया संविधान लागू किया गया। सिक्किम की जनता की इच्छायें पूरी करने के लिये आपने सितम्बर, 1974 में संविधान संशोधन विधेयक पास किया, जिसमें भारत और सिक्किम की मित्रता को मजबूत बनाने के लिए खास व्यवस्था थी और सिक्किम के प्रतिनिधियों को हमारी संसद में स्थान दिया ग ा। सिक्किम की जनता को, लोकतन्त्र हासिल करने की अपनी इच्छाओं और आशाओं को रफ्ता-रफ्ता पूरा करने में कामयाब होने पर हम बधाई देते हैं।

19 हमने, विदेशों के साथ अपने सम्बन्धों के मामले में स्वाभाविक तौर से अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के सम्बन्धों को बढ़ावा देने पर खास ध्यान दिया है।

20 हमें दिसम्बर, 1974 में भूटान के राजा का स्वागत करने का सौभाग्य मिला। इस यात्रा से भारत और भूटान के बीच आपसी दोस्ती ज्यादा गहरी और मजबूत हुई।

21 पिछली मई में बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की यात्रा के दौरान, बंगला देश के साथ एक समझौता हुआ जो हमारे निकट सम्बन्धों की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसमें सीमा के उन मसलों को हल किया गया जिन पर लगभग एक पीढ़ी से कोई फैसला नहीं हो पाता था। मुझे पू ा यकीन है कि दोनों देश समझबूझ और सहयोग की उसी भावना से कोई भी मसला, जो सामने आये, सुलझाएंगे।

22 राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में अफगानिस्तान के साथ हमारा सहयोग बढ़ा है। हम अगले महीने राष्ट्रपति दाउद के आने का इन्तजार कर रहे हैं।

23. नेपाल के प्रधान मंत्री की हाल की यात्रा के दौरान, भारत-नेपाल सम्बन्धो के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर विस्तार पूर्वक विचार हुआ। यह स्वीकार किया गया कि इसमे भारत और नेपाल दोनो का ही फ़ायदा है कि वे आदान-प्रदान और एक दूसरे के हित को ध्यान मे रखते हुए बाईलैट्रल सम्बन्धो को मजबूत बनाने की कोशिश करे।

24. मुझे इस बात पर खास तौर मे सतोष है कि कच्चातीवू के मसले पर, पाक के मुहाने की समुद्री सीमा और श्रीलका मे रहने वाले भारतीय मूल के लोगो के दर्जे के मामले मे पुराने सवालो को मित्रतापूर्ण हल किया गया जिससे श्रीलका और भारत की दोस्ती के ताल्लुकात और मजबूत हुए।

25. मालदीव और भारत के प्रधान मन्त्रियो की एक दूसरे के देश की यात्रा से दोनो देशो के बीच मित्रता के सम्बन्ध मजबूत हुए।

26. मारिशस के प्रधान मत्री सर शिवसागर रामगुलाम की यात्रा से, उस देश के साथ हमारे निकट सम्बन्ध और मजबूत होने मे मदद मिली है।

27 अप्रैल, 1974 मे बर्मा के राष्ट्रपति ने-विन की सदभावना यात्रा से आपसी सहयोग और समझबूझ को बढावा मिला है।

28. पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाने की दिशा मे कई कदम उठाये गए है। प्रगति धीमी हुई है, लेकिन निराशाजनक नही है। दोनो देशो के बीच डाक-सेवा, टेली-कम्यूनिकेशन, यात्रा-सुविधा और व्यापार फिर मे शुरू करने पर समझौते हुए है। हमें आशा है कि एक दूसरे से बातचीत करके और शान्ति-पूर्ण तरीके से मतभेद दूर करने के अच्छे रवैय्ये मे तेजी आएगी और पाकिस्तान यह समझने की कोशिश करेगा कि मुख्तलिफ जरियो से हथियार जमा करके अपने आप को फिर से लैस करना बेसूद है, क्योकि इससे आपसी मेल-मिलाप और इस उप-महाद्वीप मे पायदार अमन कायम करने मे रुकावट आयेगी।

29. इन्डोनेशिया के साथ काटिनैन्टल शैल्फ बाऊन्ड्री एग्रीमेंट हुआ है। दिसम्बर 1974 मे मलयेशिया के राजा और रानी का स्वागत करने का हमे फख्र हासिल हुआ। उनकी यात्रा से हमारे दोनो देशो के बीच मित्रता और समझबूझ बढने मे मदद मिली।

30. पूर्वी एशिया के देशो के साथ हमारे राजनीतिक और आर्थिक सम्बन्धो की रफ्तार बढी है। जापान के साथ हमारे सम्बन्ध मित्रतापूर्ण बने हुए है और हमारे व्यापार सम्बन्ध बढते जा रहे है।

31 जैसा आप जानते ही है हमारी सरकार दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार के साथ औपचारिक तथा और ज्यादा सीधा सम्बन्ध कायम करने के उपाय कर रही है।

32. अरब देशो के साथ हमारे पुराने ताल्लुकात बराबर की जिम्मेदारी और निकट सहयोग के आधार पर बढते जा रहे है। हमारे और इराक, सूडान, अरब गणराज्य, सयुक्त अरब लघु गण राज्य जैसे कई अरब देशो के बीच बडे से बडे प्रतिनिधि मण्डलो की यात्राओ के दौरान हमने अपनी सामान्य नीतियो पर विचार-विमर्श किए और आर्थिक तथा तकनीकी क्षेत्र मे कई समझौते हुए। पश्चिम एशिया की हालत गहरी चिन्ता का कारण है। पश्चिम एशिया मे स्थायी शान्ति तब तक नही आ सकती जब तक फिलिस्तिनियो के साथ इन्साफ नही किया जाता और हमला करके हथियाई गई अरबो की जमीन को खाली नही किया जाता। हम युनाइटेड नेशन्स मे फिलि-स्तीन मुक्ति सगठन की मौजूदगी का स्वागत करते है।

33. हमारी प्रधान मत्री की ईरान यात्रा और ईरान के शहशाह की भारत

यात्रा से दोनो देशो के बीच सम्बन्ध और ज्यादा मजबूत हुए। हमने लम्बी अवधि वाली कई परियोजनाओ पर सहमति जाहिर की है जो आर्थिक और दूसरे क्षेत्रो में दोनो देशो को और निकट लाएगी।

34 दुनिया मे मुक्ति ओर स्वतन्त्रता की दिशा मे एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना पुर्तगाल सरकार म परिवर्तन था। भारत और पुर्तगाल के बीच डिप्लोमैटिक सम्बन्ध फिर कायम करने पर एक समझौता हो गया है। हम उस देश के साथ मित्रता और सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत का स्वागत करते है।

35 स्वतन्त्रता की दिशा मे अफ्रीकी लोगो की कामयाबी से एक नया युग शुरु हुआ है। पुर्तगाल की कुछ कालोनिया स्वतन्त्रता के द्वार तक आ पहुची है और कुछ मे यह प्रोसैस शुरु हो गया है। साफ तौर से इन घटनाओ का रोडशिया के गैर-कानूनी शासन पर असर पडा है, हमे इस बात मे कोई सदेह नही कि जिम्बाबवे मे भी बहुमत शासन की स्थापना के लिए एक समझौता हो जाएगा और भेदभाव का अन्त होगा। दक्षिण अफ्रीका इस असर से बचा नही रह सकता। हमे पूरी उम्मीद है कि इन वाक्यात की तर्क सगति और इसके नतीजे, जिन्हे टाला नही जा सकता, कलोनियलिज्म और जातिवाद के इस आखिरी गढ को साफ नजर आने लगेंगे और मानवीय स्वतन्त्रता के दमन और अन्य प्रकार के अत्याचारो का खात्मा होगा जिन के कारण मुहज्जब दुनिया ने उन्हे सेन्शर किया है।

36. जाम्बिया के राष्ट्रपति डा० केनेथ कौडा और तनजानिया के उप-राष्ट्रपति श्री कवावा की यात्राओ से भारत और उन देशो के बीच आर्थिक व तकनीकी सहयोग और मजबूत हुआ है।

37. आर्थिक और तकनीकी सहयोग के एशिया, अफ्रीका और लातिन अमरीका के विकासशील देशो के साथ हम अपने सम्बन्ध मजबत करना चाहते है। हमने कई क्षेत्रो में एक्सपरटाइज का विकास किया है और हमारे यहा सिखाई हुई और तजुर्बेकार मानव-शक्ति का विशाल भण्डार है और इस प्रकार आर्थिक विकास की दिशा में सहयोग के लिए विकासशील मित्र देशो की मागो को पूरा करने मे हममे क्षमता है। इसी प्रकार इनमे से कई देश कई तरह से हमारी मदद कर सकते है। तेल की स्थिति का एक पॉजिटिव पहलू यह है कि इससे विकासशील देशो मे आपसी सहयोग की सम्भावनाए बढी है।

38 सभी राष्ट्रो के बीच मित्रता और नान-एलाइन्मैन्ट की हमारी नीति, और इस सब काटिनेट मे सामान्य स्थिति लाने का प्रोसैस तेज करने की हमारी पहल का सोवियत रूस द्वारा समर्थन किए जाने की हम बडी सराहना करते है। भारत-रूस सहयोग सभी क्षेत्रो मे बढ रहा है।

39 1974 मे, बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, जर्मन जनवादी गणराज्य और हगरी के प्रधान मन्त्रिया का स्वागत करने का हमे साभाग्य मिला। इन नेताओ के साथ विचार-विमर्श से हमारी आपसी समझबूझ बढी है।

40 नॉन-एलायड मूवमैट से और युनाइटड नेशन्स और दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय मचो पर, भारत और युगोस्लाविया ने निकट सहयोग बनाए रखा है।

41 अक्तूबर, 1974 मे डा० हेनरी किसिंजर की भारत यात्रा के दौरान, भारत और सयुक्त राज्य अमरीका के बीच बेहतर समझबूझ और परिपक्व सम्बन्ध की आपसी इच्छा जाहिर की गई थी। एक सयुक्त भारत-अमरीका आयोग की स्थापना की गई है, जिससे सहयोग के लिये सस्थागत आधार

मिलेगा । हमें आशा है कि संयुक्त राज्य अमरीका इस सब-काटिनेंट में आम हालात पैदा करने की दिशा में हमेशा कोशिश करता रहेगा और ऐसा कोई कदम नही उठाएगा जिससे इस पर उल्टा असर पडे ।

42. यूरोपियन इक्नामिक कम्युनिटी विकास की समस्याओ के प्रति अधिक प्रगतिशील और उदार पालीसी अपना रही है । भारत का एक तिहाई मे ज्यादा व्यापार इस कम्युनिटी के मुल्को के साथ है और हम उनके साथ सहयोग बढाने के लिए ख्वाहिशमन्द है ।

43 आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ हमारे सम्बन्ध, एशियाई प्रश्नो पर बढती हुई समझबूझ के आधार पर निकट और खुशगवार बने रहे है । ये दोनो देश हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र बनाए रखने की जरूरत के सम्बन्ध मे, तटवर्ती राज्यो की चिन्ता से सहमत है । यह एक ऐसा मामला है जिसे हम बहुत महत्व देते है ।

44 हमारा विश्वास है कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक-व्यवस्था का सकट और विकासशील देशा की समस्याए तभी दूर होगी जबकि सारे विश्व मे शाति रहे और तनाव न हो ।

45 माननीय सदस्यगण, इस अधिवेशन मे आप आमदनी और खर्च के ब्योरे तथा अगले माली साल के अनुदानो की मागो पर विचार करेगे, जो अर्थ-व्यवस्था को और पायदार तथा एक निश्चित दिशा देने के नजरिये से महत्वपूर्ण है । बये लैजिस्लेटिव उपायो में जो आपके सामने पेश किये जाएगे, सबसे महत्वपूर्ण वह है जिसका सम्बन्ध अर्बन लैड की सीलिग से है । आपके सामने कई चरणो में 34 बिल विचार के लिए है इनमे से कुछ का बहुत महत्व है । आपके आगे एक सम्पूर्ण और कठिन प्रोग्राम है । मैं आप सबसे अपील करता हू कि तलख बहस मुबाहसा और आन्दोलनो पर राष्ट्र की शक्ति जाया न करें, बल्कि भारत की जनता को, जिनमें चुनौतियो का मुकाबला करने की पूरी क्षमता है, रचनात्मक और साहसपूर्ण नेतृत्व दे

मै आपके प्रयासो की सफलता की कामना करता हूं ।

Honourable Members,

I welcome you all and summon you to another year of hard work in the service of the nation

2 We begin the year on a confident note, having responded with determination to the unforeseen and stupendous challenges of the last four years In the face of continuing rise in prices, the foremost concern of Government in 1974 was to impart a measure of stability to the economy Government adopted a comprehensive strategy to control inflation and this was put into operation from July, 1974

3 Besides increased mobilisation of resources and economies in non-Plan expenditure, money supply was restricted through an appropriate monetary policy A vigorous drive was launched against economic offences like smuggling, hoarding and tax evasion and against spurious units indulging in malpractices in scarce materials Consumer expenditure was restrained by limiting dividend incomes and impounding increases in wages and salaries and a part of additional dearness allowance Public distribution was strengthened and arrangements were made for adequate import of foodgrains and essential raw materials and commodities The annual plan for 1974-75 was reviewed and outlays on the core sectors were raised to boost production Vigorous action was also taken to improve utilisation of capacity in power plants, rail transport, coal production, steel plants and other public sector industries.

4. This concerted action began to yield results towards the end of September, 1974. Despite an unsatisfactory kharif crop caused by poor rainfall in many States, prices began to fall and there has been a weakening of the inflationary forces. The availability of essential goods has generally improved. The general outlook for the rabi crop is good.

5. Production in public enterprises has shown a significant rise in the first nine months of this financial year. Fourteen per cent more electricity is being produced by thermal plants and improvement of thirty-four per cent in the production of power by DVC plants merits special mention. Since shortage of power still persists in a number of States, high priority is being given to the completion of power projects. About two million KW of power capacity is being added in 1974-75 and another three million in the coming year. Ten million tonnes more coal will be produced this year. Steel production is going up and public sector engineering industries are doing remarkably well. More railway wagons are being moved daily.

6. I congratulate workers, farmers and other sections of the people for the determination, courage and identity with national purpose shown by them in supporting the Government's programme of economic stabilisation.

7. Government is aware that there is no room for complacency as there are still sizable imbalances between supply and demand in several important sectors of the economy. The international economic situation is also full of uncertainties

8. The monetary and fiscal measures and the action against economic offences will be continued with vigour. Simultaneously, Government will intensify measures to remove limitations in the infrastructure and to increase production in vital sectors. In the international sphere, we shall continue to work for the evolution of a just and viable economic order in co-operation with developing countries as well as developed countries which have shown understanding of our problems.

9. We have been hit hard by the sudden and large increase in the prices of oil, food and fertilizers. Articles of common consumption have been affected and great hardship has been caused to the people. There is a very heavy draft on foreign exchange. Even a significant increase in our export earnings—in the first eight months of 1974-75, the increase was 36 per cent—is not adequate to fill the gap. Special efforts and arrangements are necessary to deal with the problems of oil-importing developing countries. Some of the oil exporting countries have helped us in this regard. There has also been some action at the international level. But these measures fall short of the needs of the situation. The severe damage caused to the economies of developing countries has to be recognised and redressed through purposeful co-operative effort on a global scale. We shall continue to take appropriate initiatives in this direction both through bilateral negotiations and in international forums.

10. In addition to the emphasis on increased production and use of coal, we are going ahead with oil exploration on an urgent basis. The recent discoveries in the offshore Bombay High structure are promising. Government has decided that this oil field should be developed to the production stage with the greatest expedition. It is being planned that the first stage of production should begin in 1976 and that in another four years, the production from this area should go up to 10 million tonnes. The future outlook for production of oil from offshore and onshore areas is reassuring.

11. There is understandably some anxiety about the Fifth Five Year Plan. A plan has a framework and

a coherent system of objectives as well as a detailed programme indicating targets and the availability of resources necessary for achieving them. The basic framework of the draft Fifth Plan and its objectives remain unaltered. At the same time, the extraordinary developments in the economic sphere, both external and internal, call for adjustments in the sequence and composition of detailed programmes. Meanwhile, the annual plan for 1975-76 is being prepared giving emphasis to economic stability and increased investment in crucial sectors—agricultural production, irrigation, fertilisers, power, steel, coal and oil exploration. It is also proposed to intensify development programmes benefiting the less developed regions and the weaker sections of the community including scheduled castes and scheduled tribes. Programmes under the Small Farmers Development Agency and those for Marginal Farmer and Agricultural Labour, drought prone areas and the command areas are being accelerated.

12. A review of the national effort in 1974 will not be complete without reference to the major advance that we made in the nuclear field—the underground experiment of 18th May, 1974. I congratulate our nuclear scientists and engineers on this signal achievement. We have reaffirmed our determination to use nuclear energy only for peaceful purposes and our reasons for undertaking the experiment have been appreciated by most countries. Government will continue to give a place of importance to science and technology as instruments of economic advancement.

13. I am happy that the extensive talks held between the representatives of the Government of India and the leaders of the State of Jammu and Kashmir have yielded positive results. Government will shortly make a statement in this regard. We wish the people of Jammu and Kashmir speedy progress as an integral part of the nation.

14. Hon. Members, when the nation is straining every nerve to meet formidable challenges, it is regrettable that some groups have been doing every thing possible to weaken the will of the people and to sap the cohesion and unity of purpose, so vital at such times. They claim that their object is total revolution and elimination of corruption but the actual result is violence and disruption of political and economic life. Government is fully conscious of the need for reform in several spheres of national life and welcomes suggestions. Indeed, our objective is to bring about a transformation of society and to change the quality of life. It is the essence of the democratic system that changes are brought about through the widest possible discussion and agreement. Mere disruption of the existing system or institutions, with no better and workable alternative, will only endanger the stability and progress of our country.

15. Government is anxious that the Lokpal and Lokayukthas Bill, which has been before you for some time now, should be considered and finalised during this year. This will provide the legal framework to deal with corruption among political executives and in administration. Government will shortly discuss with the leaders of political parties proposals for changes in the electoral law. Whatever reforms are introduced should be such as will command the widest possible public support and consolidate the system of parliamentary democracy enshrined in our Constitution.

16. As regards education also, Government has worked out programmes for reform of the examination system, vocationalisation of secondary education, regulation of enrolment for higher education and introduction of a system of non-formal education. Previous experience shows that schemes of education reform fail to gather momentum unless they are widely accepted by State Governments, teachers, parents and students.

Meanwhile, considerable disturbance is caused in the scholastic career of millions of young people. State Government have taken steps to implement some of the programmes of reform. We are anxious that more far-reaching changes in the educational system are introduced through the widest possible discussion.

17. I appeal to all sections of the people to ponder seriously over these fundamental issues, offer positive and constructive suggestions and criticisms and cooperate with the Government in working out national solutions. This is the democratic way. Any other way will lead only to chaos and disillusionment.

18. I may now refer to developments in Sikkim. Elections were held there for the first time in April, 1974. On the unanimous resolution of the elected Assembly, a new constitutional framework was promulgated by the Chogyal on the 4th July, 1974. Responding to the expressed wishes of the people of Sikkim, you approved a Constitution Amendment Bill in September, 1974 incorporating specific provisions for strengthening Indo-Sikkim relationship, including the representation of Sikkim in our Parliament. We congratulate the people of Sikkim on the progressive realisation of their democratic aspirations.

19. In our relations with the outside world, we have naturally continued to attach special importance to the consolidation of friendly relations with our neighbours.

20. In December, 1974, we had the privilege of welcoming the King of Bhutan. The visit served to consolidate further traditional warm friendship between India and Bhutan.

21. An event of significance in our close relations with Bangladesh was the conclusion of an Agreement, during the visit of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in May last, settling the land boundary questions which had remained unresolved for nearly a generation. I feel confident that the two countries will resolve any issue which may arise in the same spirit of understanding and co-operation.

22. There has been increasing co-operation with Afghanistan in the political and economic fields. We look forward to the visit of President Daoud next month.

23. During the recent visit of the Prime Minister of Nepal, there was a detailed exchange of views on various aspects of Indo-Nepal relations. It was recognised that it was in the interest of both India and Nepal to do their utmost to strengthen bilateral relations keeping in view, at all times, the principles of reciprocity and mutual benefit.

24. I am particularly gratified that the cordial relations between Sri Lanka and India were further strengthened by the amicable settlement of the long outstanding questions of Kachhativu and the maritime boundary in the waters of the Palk Bay as well as the status of persons of Indian origin in Sri Lanka.

25. The exchange of visits between Prime Ministers of Maldives and India strengthened the friendly relations between the two countries.

26. The visit of the Prime Minister of Mauritius, Sir Seewoosagur Ramgoolam, helped to further strengthen our close ties with that country.

27. The goodwill visit of President Ne Win of Burma in April, 1974 consolidated our mutual co-operation and understanding on bilateral and international questions.

28. Several steps were taken towards normalising relations with Pakistan. Progress has been slow but not discouraging. Agreements have been worked out for the resumption of postal services, telecommunication links travel facilities and trade between the two countries. We hope that the

healthy trend towards settling differences bilaterally and through peaceful means will gather momentum and that Pakistan will realise the futility of rearming itself by procuring arms from various sources, as this will hinder reconciliation and the establishment of durable peace of the subcontinent.

29. A continental shelf boundary Agreement was concluded with Indonesia. We were honoured to receive the King and Queen of Malaysia in December, 1974. Their visit served to underscore the friendship and understanding between our two countries.

30. There is a marked increase in the tempo of our political and economic relations with the countries of East Asia. With Japan, our relations remain friendly and our trade ties are growing.

31. As you are aware, Government is taking steps to establish formal contacts and more direct relations with the Provisional Revolutionary Government of South Vietnam.

32. Our traditional ties with the Arab World have continued to be marked by solidarity and close co-operation. We have had exchange of visits at the highest level with a number of Arab countries such as Iraq, Sudan, the Arab Republic of Egypt and the United Arab Emirates, during which we have had discussions on our common policies and have entered into a number of agreements in the economic and technical fields. The situation in West Asia is a cause for grave anxiety. Lasting peace in West Asia will not be achieved until justice is assured to Palestinians and Arab territories seized by aggression are vacated. We welcome the presence of the Palestine Liberation Organisation in the United Nations.

33. Our Prime Minister's visit to Iran and the visit of the Shahanshah of Iran to India contributed to the strengthening of relations between the two countries. We have agreed on a number of long term projects which should bring our countries closer in economic and other fields.

34. An event of great significance to the cause of liberty and freedom in the world was the change in the Government in Portugal. An Agreement has been entered into for resumption of diplomatic relations between India and Portugal. We welcome the opening of a new chapter of friendship and co-operation with that country.

35. In the progress of the African peoples towards independence, a new era has dawned. Some of the Portuguese colonial territories are on the threshold of independence, in others the process has begun. Apparently, these events are having an impact on the illegal regime in Rhodesia; we have no doubt that in Zimbabwe too a settlement will be reached for the establishment of majority rule and the end of discrimination. South Africa cannot remain unaffected and we sincerely hope that the logic of these events and the inevitability of the outcome will be clear to this last bastion of colonialism and racialism and that there will be an end to the suppression of human liberty and other forms of persecution which have earned them the censure of the civilised world.

36. The visits of Dr. Kenneth Kaunda, President of Zambia and Mr. Kawawa, Vice-President of Tanzania further strengthened economic and technical co-operation between India and these countries.

37. We wish to strengthen our ties with the developing countries of Asia, Africa and Latin America through economic and technical co-operation. We have developed expertise in a number of fields and have a large reserve of trained and experienced man-power and thus have the capacity to respond to the requests of friendly developing countries for co-operation in economic development. Similarly, many of these countries

can help us in several ways. A positive aspect of the oil situation is the enormous possibilities it has opened up for mutual co-operation between developing countries.

38. We greatly appreciate the support given by the USSR to our policy of non-alignment and friendship among all nations and to the initiatives taken by us to expedite the process of normalisation on the sub-continent Indo-Soviet co-operation is growing in all fields.

39. During 1974, we had the privilege of receiving the Prime Minister of Bulgaria, Czechoslovakia, the GDR and Hungary. The exchange of views with these leaders has deepened our mutual understanding.

40. India and Yugoslavia have continued their close co-operation in the Non-aligned Movement and at the United Nations and other international forums.

41. During the visit of Dr. Henry Kissinger to India in October, 1974, there was expression of mutual desire for better understanding and a mature relationship between India and the United States of America. An Indo-US Joint Commission, which will provide an institutional framework for co-operation, was formed. We hope that the United States will continue to support the trend towards normalisation on the sub-continent and will not take any steps which may adversely affect it.

42. The European Economic Community is taking a progressively more liberal attitude towards the problems of development. Over a third of India's trade is with the countries of the Community and we look forward to increasing co-operation with them.

43. Relations with Australia and New Zealand have remained close and cordial based on a growing understanding on Asian questions. Both these countries have shared the concern of the littoral States regarding the need to maintain the Indian Ocean as a Zone of Peace, a matter to which we attach very great importance.

44. We are convinced that the crisis in the international economic order and the enormous problems facing developing countries can be resolved only if there is peace and absence of tension throughout the world.

45. Hon'ble Members, during this Session you have to consider the Statement of Receipts and Expenditure and the Demands for Grants for the coming financial year, which is crucial from the point of view of further stabilising the economy and giving it a firm direction. Of the new legislative measures that will be presented to you, the most important one deals with the imposition of ceiling on urban land. You have as many as 34 Bills pending before you in various stages. Some of these are of far-reaching importance. You have a full and strenuous programme ahead of you I appeal to one and all not to fritter away national energies on acrimonious controversies and agitations but to give a constructive and confident lead to the people of India, who have a proven capacity to overcome challenges.

I wish you success in your endeavours.

Jai Hind.

श्री मधु लिमये (बांका) अध्यक्ष महोदय मेरा व्यवस्था का सवाल है। मैं नं० 2 पर व्यवस्था के सवाल पर खड़ा हुआ हूं

व्यवधान

MR. SPEAKER: No points of order can be raised, when the President's Address is just laid on the Table. You can raise it when it comes for discussion. I do not allow it. Nothing will go on record. Please do not disturb the House.

श्री मधु लिमये : इनमें डिस्टर्ब करने का सवाल नहीं है। मैं अपने अधिकार में हूं